भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1104

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

मोबाइल निगरानी प्रणाली का विकास

1104. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए मोबाइल निगरानी प्रणाली या पोर्टल विकसित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चंदौली जिले में किसानों को खाद वितरण प्रणाली में तकनीकी खामियों या डीलरों की लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ और यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) क्या सरकार ने डीएपी और दूसरे उर्वरकों की कमी के कारण धान की पैदावार में होने वाली संभावित कमी के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो अनुमानित कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उर्वरक विभाग ने वर्ष 2016 से एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) लागू की है। यह उत्पादन/आयात बंदरगाह से लेकर जिला गोदामों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं तक उर्वरकों के उत्पादन, प्रेषण, प्राप्तियों और बिक्री की निगरानी करता है। उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए, अंतिम बिक्री केंद्र (खुदरा केन्द्रों) पर पावती दी जाती है। स्वीकृत स्टॉक की बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, हालांकि बिक्री केंद्र (पीओएस) की मध्यस्थता से खरीदार के आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा बिक्री की जाती है। इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने एक डैशबोर्ड भी विकसित किया है जिसे अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा https://urvarak.nic.in पर एक्सेस किया जा सकता है। डैशबोर्ड को राज्य कृषि विभाग, जिला कलेक्टर और राज्य विपणन संघ जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा सहज निगरानी की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। राज्य सरकारें कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए आईएफएमएस और ई-उर्वरक डैशबोर्ड पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की भी निगरानी कर रही हैं।

(ख): जी, नहीं।

(ग): चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान देश में डीएपी और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है।

****